साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गाँव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

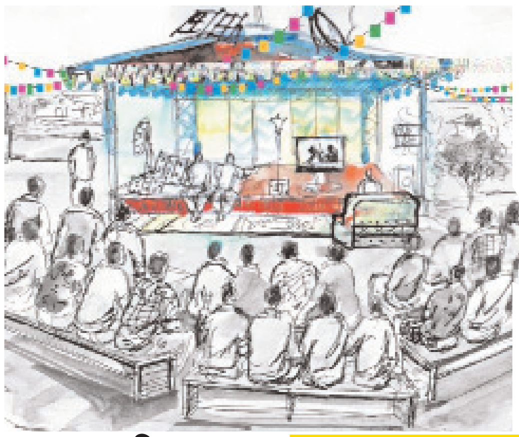

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 21 जून 2021, वर्ष-7, अंक-12

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

» कैबिनेट की मुहरः कंज्यूमर को सस्ती बिजली के लिए 14,500 करोड़ रुपए का अनुदान

» धान मिलर को 50 से लेकर दो सौ रुपए क्विंटल मिलेगी अब प्रोत्साहन राशि

» मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी

एमपी में धान मिलिंग को बढ़ावा देने सरकार बनाएगी नीति

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल

प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी गई 37.26 लाख टन धान की मिलिंग कराने में आ रही समस्या का रास्ता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने निकाल लिया। सीमावर्ती राज्यों के मिलर से भी मिलिंग कराई जाएगी। वहीं, प्रदेश के मिलर को 50 से लेकर दो सौ रुपए तक प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि शर्तों के साथ दी जाएगी। इस निर्णय के आधार पर ही अब मिलिंग का काम कराया जाएगा।

वहीं, धान के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए तय किया गया कि मिलिंग को बढ़ावा देने और एथेनॉल से जुड़े उद्योगों के लिए नीति भी बनाई जाएगी। बिजली कंपनियों को घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को दरों में छूट देने के लिए सरकार द्वारा अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। बैठक में धान की मिलिंग के मुद्दे पर खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने प्रस्तुतीकरण किया। इसमें प्रदेश में लगातार बढ़ रही धान की खेती और उत्पादन को देखते हुए मौजूदा मिलिंग की क्षमता, अन्य राज्यों के प्रविधान और विभिन्न विकल्पों के बारे में बताया गया। साथ ही

कहा कि मिलिंग की गति बेहद धीमी होने की वजह से अन्य राज्यों के मिलर को भी आमंत्रित किया था पर उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। इसके मद्देनजर प्रदेश के मिल संचालकों से दोबारा मिलिंग के लिए दरें बुलाई थी, जो औसत 246 रुपए प्रति क्विंटल प्राप्त हुई। इस स्थिति को देखते हुए प्रोत्साहन राशि 50 रुपए के अतिरिक्त 50 से लेकर दो सौ रुपए प्रति क्विंटल देने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे बैठक में मंजूरी दी गई। यह व्यवस्था सिर्फ खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान की मिलिंग के लिए लागू रहेगी। यदि समय-सीमा में इसके बाद भी मिलिंग नहीं हो पाती है तो फिर बची हुई धान को लेकर कैबिनेट में अलग से निर्णय किया जाएगा।

धान मिलिंग के विकल्प

- पूरा चावल नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करने पर प्रति क्विंटल 50 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
- 80 फीसदी चावल नागरिक आपूर्ति निगम और 20 फीसदी भारतीय खाद्य निगम को देने पर प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त पचास रुपए प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि मिलेगी।
- 40 प्रतिशत चावल नागरिक आपूर्ति निगम और 60 प्रतिशत भारतीय खाद्य निगम को देने पर प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त 150 रुपए प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि मिलेगी।

बिजली कंपनियों को 20 हजार करोड़ का अनुदान

घरेलू और कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय दर से कम पर बिजली देने के एवज में बिजली कंपनियों को वर्ष 2020-21 के लिए 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुदान दिया जाएगा। इंदिरा गृह ज्योति योजना के उपभोक्ताओं के लिए चार हजार 945 करोड़, दस हार्स पावर तक और अधिक क्षमता कृषि पंप उपयोगकर्ता किसानों के लिए नौ हजार 773 करोड़, एक हेक्टेयर तक भूमि वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के पांच हार्स पावर तक कृषि पंप उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली देने के लिए चार हजार 323 करोड़ रुपए का अनुदान कंपनियों को दिया जाएगा।

धान से एथेनॉल बनाने और मिलिंग की क्षमता बढ़ाने को लेकर नीति बनाने के निर्देश लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग को दिए हैं। किसानों से खरीदे गए धान के लिए तीन स्लैब बनाने का निर्णय लिया गया है। यह स्लैब 50 से लेकर 200 रुपए के बीच में होंगे। बैठक में मुख्य रूप से वर्ष 2020-21 में सस्ती बिजली के लिए वितरण कंपनियों को 14 हजार 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री एवं प्रवक्ता, मप्र शासन

प्रदेश के सरकारी गोदामों में अनाज रखने की जगह नहीं

सड़ गया हजारों क्विंटल धान

» ओपन केप में रखा करोड़ों रुपए की धान हो गई बर्बाद

» 30 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की मिलिंग अटकी

» कटनी-शहडोल में सड़ रहा 81.86 करोड़ रुपए का धान

» रखरखाव में खुली जिम्मेदार अफसरों की खुल गई पोल

अरविंद मिश्र, भोपाल

मध्यप्रदेश में सरकार हर साल किसानों से रिकॉर्ड तोड़ अनाज खरीद रही है, लेकिन उन अनाजों को रखने के लिए गोदामों में जगह नहीं है। इस कारण उन्हें ओपन केप में रखा जा रहा है। ओपन केप में रखे अरबों रुपए के धान और गेहूं हर साल सड़ जाते हैं। इस बार कटनी और शहडोल जिले में ओपन केप में रखा 81.86 करोड़ का 3.38 लाख क्विंटल धान सड़ने का मामला सामने आया है।

22 मई को मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में राइस मिल एसोसिएशन कटनी ने चेताया था कि वर्ष 2020-21 में खरीदकर ओपन केप में रखा 14 लाख क्विंटल धान भी बारिश में बर्बाद हो सकता है। इसके बावजूद अधिकारी हरकत में नहीं आए। जबकि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कहा था कि सड़ रहे अनाज को गरीबों में बांट दिया जाना चाहिए। उधर, धान की मिलिंग कर चावल निकालने को लेकर राज्य सरकार और मिलर्स के बीच रेट पर सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में 30 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की मिलिंग अटकी हुई है। प्रदेश से बाहर के मिलर्स से मिलिंग कराने के फैसले के बाद भी सफलता नहीं मिली है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को रेट व अन्य मामलों के लिए कैबिनेट की अनुमति का इंतजार है। बारिश शुरू होने से धान खराब होने की आशंका भी बढ़ गई है।

अब तो बोरियों में होने लगा अंकुरण

शहडोल जिले की लालपुर हवाई पट्टी स्थित अस्थाई केप में 2020-21 में रखे धान को सहेज पाने में प्रशासन नाकाम रहा। यहां रखा करीब 10 हजार क्विंटल धान सड़ चुका है। नमी की अधिकता के कारण धान अंकुरित होकर बोरियों से बाहर आ गए हैं। एक साल में धान लगातार खराब होता रहा और अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। धान खराब होने की वजह नान के साथ फूड विभाग और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की लापरवाही को माना जा रहा है। खरीदी के समय ही अनेक स्थानों की धान भींग चुका था, जिसे नमी हालत में ही रखवा दिया गया।

चबूतरे का निर्माण नियमानुसार नहीं

ओपन केप में रखे धान का नान व फूड ने पड़ताल नहीं की। अस्थाई केप के लिए बनाए गए चबूतरे में नियमानुसार इलाहाबादी व फ्लाईऐश ईंटों का उपयोग होना चाहिए था, लेकिन जिस ठेकेदार को काम मिला। उसके द्वारा स्थानीय स्तर से गुणवत्ताहीन ईंट का उपयोग किया गया।

कटनी में मिलर्स ने खींचे हाथ

उधर, कटनी में वर्ष 2019-20 में किसानों से खरीदा गई 80 करोड़ की 3.28 लाख क्विंटल धान नान की लापरवाही के चलते बर्बाद हो गया। मझगवां बड़वारा, मझगवां फाटक एवं सलैया फाटक में रखी धान की मिलिंग से मिलर्स ने भी हाथ खींच लिए। जब मिलर्स ने मिलिंग से इनकार कर दिया, तब शासन ने खुले बाजार में बेचने टेंडर कॉल किए, लेकिन धान की दशा देखकर कोई आगे नहीं आया। नियमानुसार 3 माह के भीतर धान का उठाव कर लिया जाना था।

इनका कहना है

धान भीगा है, लेकिन, कम बोरियां भीगी हैं। जबकि, खुले आसमान के नीचे रखी धान काफी मात्रा में भीगकर अंकुरित हो गई है। शासन ने विगत वर्ष समर्थन मूल्य पर 1800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा था। जबकि परिवहन, भंडारण, खरीदी का कमीशन एवं अन्य खर्च मिलाकर धान की कीमत 2500 रुपए क्विंटल तक पहुंच जाती है।

कमलेश टांडेकर, जिला आपूर्ति नियंत्रण अधिकारी

कलेक्टर द्वारा टीम का गठन किया गया है। वह जांच कर कर बताएगी कि कितना धान खराब हुआ है। जहां तक बात धान उठाव की है तो मिलर से रेट तय नहीं हो पा रहा है। इसलिए समय से धान का उठाव नहीं हो पाया है। यह सही बात है कि कुछ लॉट का धान खराब हुआ। जो भी नुकसान हुआ उसके लिए वेयर हाउस से वसूली की जाएगी। यही नहीं, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

राकेश चौधरी, मैनेजर, नागरिक आपूर्ति निगम

मुख्यमंत्री शिवराज बोले

मूंग में किसान को नुकसान नहीं होने देंगे

भोपाल। ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी प्रक्रिया का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारी सरकार किसानों के पसीने की पूरी कीमत देगी। राज्य सरकार खेती को फायदे का धंधा बनाने, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए कठिन परिश्रम से ली गई ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा आठ जून को की गई। युद्ध स्तर पर पंजीयन हुआ और अब खरीदी की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। सीएम ने कहा कि बरसात में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी कठिन कार्य है। किसानों ने गर्मी के महीनों में परिश्रम कर मूंग का रिकार्ड उत्पादन किया है। अधिक उत्पादन के कारण दाम कम होने के फलस्वरूप समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से मूंग के दाम स्थिर हुए हैं। वर्षा ऋतु को देखते हुए ऐसे स्थानों पर ही खरीदी केन्द्र बनाए गए हैं जहां मूंग को भीगने से बचाया जा सकेगा।

इनका कहना है

प्रदेश में 6 लाख 82 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मूंग लगाई गई है। अब तक ढाई लाख के करीब किसानों ने पंजीयन करा लिया है। सर्वाधिक पंजीयन कराने वाले प्रथम पांच जिले क्रमश: होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, सीहोर और जबलपुर हैं। प्रति क्विंटल 7,196 रुपए समर्थन मूल्य की घोषणा से किसानों को बड़ी राहत मिली है।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

दुर्लभ आमों की रखवाली में तैनात चार गार्ड और नौ डॉग

» संकल्प ने बंजर पड़ी जमीन पर खुले में तैयार की बगिया

» आम की जापानी प्रजाति का ताईयो नो तमागो है नाम

संवाददाता, जबलपुर

मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से तकरीबन 40 किमी दूर चरगवां क्षेत्र के एक फार्म हाउस में पके आम इन दिनों चर्चा में है। फार्म हाउस के मालिक संकल्प परिहार का दावा है कि इस आम की कीमत दो लाख 70 हजार रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। इस महंगी वैरायटी को ताईयो नो तमागो के नाम से जाना जाता है। यह मूलत: जापान में ही पाई जाती है। वहीं जवाहरलाल कृषि विवि जबलपुर के हार्टिकल्चर विज्ञानी प्रो एसके पांडे ने फार्म में लगे आमों को देखने के बाद आम के दामों व वैरायटी के दावों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि डीएनए के मिलान के बाद ही इसकी सत्यता प्रमाणित की जा सकती है। बहरहाल दावे की सत्यता जब सामने आएगी, तब आएगी, अभी तो इस आम की रखवाली की व्यवस्था भी चर्चा में है। इसके पेड़ों की रखवाली के लिए संकल्प ने चार गार्ड नियुक्त किए हैं और नौ कुत्ते पाले हैं।

52 पेड़ ताईयो नो तमागो

संकल्प का कहना है कि वे तीन साल पहले चेन्नई की एक नर्सरी से वे कई किस्मों के आम के लगभग 100 पौधे लाए थे। उनमें 52 पौधे ताईयो नो तमागो किस्म के थे। पिछले साल जापानी पद्धति के आम आने शुरू हुए। गूगल से आम की किस्म का पता लगने के बाद उन्हें इसकी कीमत का अंदाजा हुआ और उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था की।

यह है ताईयो नो तमागो

जापान के मियाजाकी शहर में आम की यह खास किस्म पैदा की जाती है। सुर्ख लाल रंग के इन आमों को दुनिया में सबसे महंगा माना जाता है। बताया जाता है कि इसके हर आम के रंग, वजन और उसमें शुगर की मात्रा का मानक तय है। इसका एक आम कम से कम 350 ग्राम का होना चाहिए और उसमें शुगर 15 फीसद या ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए तापमान और सूर्य के प्रकाश की विशेष व्यवस्था रखी जाती है। जापानी में ताईयो नो तमागो का अर्थ सूर्य का अंडा होता है।

इनका कहना है

अन्य देशों से पौधे या बागवानी से जुड़ी सामग्री लाना होता है तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, जिसमें परीक्षण कमेटी होती है। आवेदन के बाद कमेटी ही यह तय करती है कि जो पौधा अन्य देश से यहां लाया जा रहा है, वह देश के लिए उपयुक्त है या नहीं। प्रक्रिया का पालन किए बिना अन्य देश से पौधे, बीज लाना अनाधिकृत होता है।

डॉ. नवीन पटेल, अपर आयुक्त, बागवानी विभाग, केंद्रीय कृषि मंत्रालय

देश में 1200 किस्म के आम होते हैं। यह आम ताईयो तमागो किस्म का ही है, यह नहीं कहा जा सकता, जब तक कि डीएनए से मिलान न हो जाए। फार्म मालिक को इसकी किस्म के बारे में पता ही नहीं है और न ही उसने पौधे अधिकृत नर्सरी से लिए हैं। चेन्नई में कई नर्सरी संचालक, कई किस्मों को मिलाकर नई किस्म तैयार करते हैं, जिससे यह पता लगाना संभव नहीं होता है कि असल किस्म कौन सी है।

प्रो. एसके पांडे, कृषि वैज्ञानिक, जबलपुर

सोपा का अनुमान: इस साल सोयाबीन का राष्ट्रीय रकबा 132 लाख हेक्टेयर रहेगा

मप्र में सोयाबीन का होगा रिकॉर्ड उत्पादन!

संवाददाता, भोपाल

मप्र सहित देश में इस साल सोयाबीन का रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है। इससे खाद्य तेलों के महंगे आयात से राहत मिल सकती है। इंदौर स्थित सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) ने मौजूदा खरीफ सत्र के दौरान सोयाबीन का राष्ट्रीय रकबा 10 फीसदी बढ़कर 132 लाख हेक्टेयर के आस-पास रहने का अनुमान जारी किया है। हालांकि मप्र में बीज की कमी के कारण किसान सोयाबीन की खेती के लिए मन नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन अच्छे मानसून को देखते हुए पिछली बार की अपेक्षा इस बार सोयाबीन का रकबा बढ़ने की उम्मीद है। सोपा के के चेयरमैन डेविश जैन ने बताया कि हमें लगता है कि इस बार देश में सोयाबीन के रकबे में करीब 10 फीसदी का इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 के खरीफ सत्र के दौरान देश में करीब 120 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया था, जबकि इसकी पैदावार 105 लाख टन के आस-पास रही थी। जैन ने कहा, हमें लगता है कि खासकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसान उपज के बेहतर दाम की उम्मीद

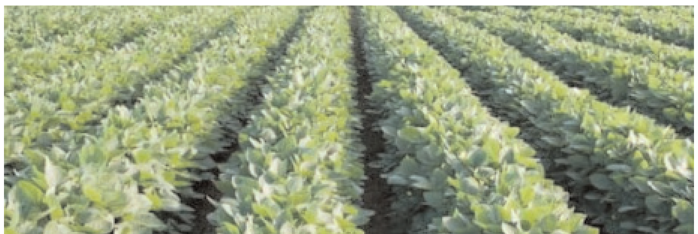

में खरीफ की अन्य फसलों के मुकाबले सोयाबीन उगाने को तरजीह देंगे।

समर्थन मूल्य 70 रुपए क्विंटल बढ़ा

केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के खरीफ विपणन सत्र के लिये सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 3,950 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। एमएसपी की यह दर पिछले सत्र के मुकाबले 70 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। इससे पहले कृषि मंत्रालय ने अपने अनुमान में बताया था कि इस बार तिलहनी फसलों की पैदावार में बंपर बढ़त होगी। मंत्रालय के मुताबिक, इस साल तिलहन के पैदावार में 33 लाख 46 हजार टन से अधिक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस बार देश में तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 65 लाख 65 हजार टन होने का अनुमान है। बीते साल तिलहन की उपज 3 करोड़ 32 लाख 19 हजार टन रही थी।

सोयाबीन की उपज ज्यादा होगी

इस बार सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक, देश भर में खरीफ सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 34 लाख 14 हजार टन से ज्यादा हो सकती है। जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1 करोड़ 12 हजार टन रही थी। वहीं, खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों को तिलहनी फसलों की रकबे में बढ़ोतरी को एक कारण माना जा रहा है। बीते एक साल में खाने के तेल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। माना जा रहा है कि इस बार किसानों को तिलहन का अच्छा दाम मिला है। इसी वजह से वे खरीफ सीजन में जमकर बोवनी कर रहे हैं।

सरसों, शहद, आलू और अमरूद तैयार करेंगे अब किसान

मुरैना के किसानों की आय में होगा इजाफा

मुरैना। उद्यानिकी से जुड़े किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें आधुनिक तकनीक से फसल उत्पादन लेने व सरसों, शहद, आलू व अमरूद के उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सेंथरा अहीर पोरसा में 30 लाख की लागत से किसान प्रशिक्षण केंद्र बनवाया जा रहा है। इस अभिनव पहल के जरिए किसान अपनी आमदनी में इजाफा कर सकेंगे। मुरैना जिले में डेढ़ लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सरसों का बंपर उत्पादन हो रहा है। उन्नत बीज से उपजाई सरसों में 40 प्रतिशत तक तेल की मात्रा मिल रही है। इसलिए उद्यानिकी विभाग सरसों उत्पादक किसानों को तेल उत्पादन की छोटी-छोटी इकाईयां संचालित करने के लिए तैयार करेगा। ऐसे किसानों को ऑइल मिल स्थापित करने के लिए 30 लाख रुपए लागत के प्लांट लगाने के लिए बैंकों से पैसा मंजूर कराया जाएगा। इसमें अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इस वर्ष 10 किसानों के लिए 10 ऑइल मिल लगाने के प्रकरण स्वीकृत कर बैंकों को भेजे हैं।

मनरेगा के तालाबों में भी होगा मछली पालन

» मत्स्य विभाग ने उपयोगी तालाबों की मांगी जानकारी
» खदानों के तालाब भी बन रहे रोजगार व आय के साधन

संवाददाता, भोपाल

अब प्रदेश में मनरेगा के तहत निर्मित तालाबों में भी मछली पालन होगा। कोरोना संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार इस योजना पर काम कर रही है। मत्स्य विभाग ने जिलों से उपयोगी तालाबों की जानकारी मांगी है। संभावना जताई जा रही है की मानसून के बाद मनरेगा तालाबों में मछली पालन शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा की है कि एक माह में एक लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब सभी विभाग इसकी तैयारी में जुट गए हैं।

तालाबों में भी उत्पादन की योजना

जिलों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अब मत्स्य विभाग मनरेगा योजना से तैयार हो रही ग्रामीण अंचल की तालाबों में भी उत्पादन की योजना तैयार कर रहा है। इनमें ऐसे तालाबों को चिह्नित किया जाएगा जिनकी जलभराव क्षमता अच्छी हो और गर्मी के दिनों में भी इनमें पर्याप्त पानी उपलब्ध हो। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश में हजारों की तादाद में ग्रामीण अंचलों में तैयार किए जा रहे या हो चुके तालाब स्थानीय ग्रामीणों के लिए जल स्रोत, जल संरक्षण के साथ साथ रोजगार व आय के साधन बन जाएंगे। साथ ही मत्स्य पालन के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। तालाबों की संख्या अधिक होने पर स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक किसान भी इस रोजगार से जुड़ सकेंगे।

विभाग जुटा रहा जानकारी

अब मत्स्य विभाग ग्रामीण अंचलों में मनरेगा योजना के तहत बन रहे तालाबों को भी मत्स्य पालन के उपयोग में लाने की तैयारी में जुटा हुआ है। कोरोना काल में वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण अंचलों में स्थानीय मजदूरों को अधिक से अधिक कार्य उपलब्ध कराते हुए रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें जिला पंचायतों द्वारा ग्रामीण अंचलों में पानी की समस्या को दूर करने और जलसंरक्षण को लेकर तालाबों के निर्माण पर भी जोर दिया गया है। जिसके कारण पंचायत स्तर पर हजारों तालाब निर्मित और निर्माणाधीन है।

समितियां बनाकर लिया जा सकता है तालाब

बन रही योजना के अनुसार मत्स्य पालन के लिए समितियां बनाकर तालाब लिया जा सकता है। कई जिलों में मछली पालन के प्रति पुरुषों के साथ महिला समितियां भी आगे आ रही है। जिसके कारण अब मत्स्य पालन रोजगार बन गया है और इसमें काम करने वाले समिति के सदस्यों के साथ अन्य सहयोगी लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। इससे जहां पालकों की आय में वृद्धि हो रही है वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। प्रदेशभर में मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों को मत्स्य पालन के लिए तालाबों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए थे। इसके अलावा मत्स्य पालकों एवं मत्स्य पालन समितियों के सदस्यों से संपर्क स्थापित कर उन्हें मत्स्य पालन के लिए प्रोत्साहित करन के निर्देश दिए गए हैं।

गुजरात के जलदोहन से कम हो रहा नर्मदा का जलस्तर

मप्र में पेयजल सप्लाई के लिए लगाना पड़ेंगी और मोटर

संवाददाता, भोपाल

गुजरात में सरदार सरोवर बांध की नहरों के जरिए बिजली बनाकर पानी का उपयोग किया जा रहा हैं। वहीं मप्र में लिंक परियोजनाओं के माध्यम से नर्मदा नदी से पानी लिफ्ट हो रहा है। इसके चलते नर्मदा का जलस्तर कम हो रहा है। नर्मदा का जलस्तर 117 मीटर पर पहुंच गया। अगर इसी तरह नर्मदा जल का दोहन होता रहा तो मप्र में पेयजल सप्लाई के लिए मोटरें लगानी पड़ेगीं। नर्मदा का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। आगामी दिनों में वाटर लेवल और कम होने के आसार हैं। नर्मदा नदी का बेड लेवल (सतही स्तर) 112 मीटर है। पानी का लेवल इससे कम होने पर जलसंकट की स्थिति बनेगी। ऐसे में पनडुब्बी व अन्य मोटर लगाकर रिपंपिंग के जरिए पानी इंटेकवेल के पाइप तक लिफ्ट करना पड़ेगा।

लिफ्ट हो रहा पानी

नबआं कार्यकर्ता राहुल यादव ने बताया मप्र को 2024 तक नर्मदा का पानी मिलना है। अभी 1 लाख प्रति सेकंड पानी नर्मदा-शिप्रा लिंक से उठा रहे हैं। इसके अलावा नर्मदा पर नर्मदा-शिप्रा लिंक परियोजना, नर्मदा गंभीर, कालीसिंध-नर्मदा, खरगोन खंडवा सहित अन्य जिलों में 10 बड़ी लिंक परियोजना के जरिए नर्मदा से पानी लिफ्ट कर रहे हैं।

2018 में 112 मीटर पर था पानी का लेवल

अभी जलस्तर 117 मीटर है। अभी पानी और कम होने की आशंका है। अभी पंप से पानी नीचे चले गया है। इस कारण 20 फीट पाइप बढ़ाकर पानी खींचेंगे। 114 मीटर से कम लेवल पर पानी सप्लाय करने में परेशानी आती है। 2018 में जलस्तर 112 मीटर पर गया था। इस दौरान रिपंपिंग के जरिए पानी इंटेकवेल तक पहुंचाया था। नर्मदा ट्रिब्यूनल की 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मप्र को विभिन्न परियोजनाओं के जरिए 18.25 एमएफ पानी का उपयोग करना है। जबकि गुजरात को 9.00 एमएएफ, महाराष्ट्र को 0.25 एमएएफ व राजस्थान को 0.50 एमएएफ कुल 28.00 एमएएफ पानी का उपयोग करना है। मप्र अपने हिस्से के पानी का उपयोग करने के लिए प्रदेश के मास्टर प्लान 1972 के अनुसार 29 बड़ी, 135 मध्यम और 3000 लघु परियोजनाओं का निर्माण करना है। नर्मदा-गंभीर लिंक, नर्मदा-शिप्रा लिंक सहित अन्य परियोजनाओं के जरिए नर्मदा से पानी लिफ्ट किया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने प्लॉट देने के लिए हितग्राहियों को सत्यापित करने के दिए आदेश

पहली बार सरकारी जमीन के पट्टों में मिलेगा मालिकाना हक

संवाददाता, भोपाल

पहली बार सरकार जमीन के पट्टों में हितग्राही को मालिकाना हक देने जा रही है। यह पट्टे सीधे तौर पर खसरा-खतौनी में भू-स्वामी के नाम से दर्ज कर दिए जाएंगे। इससे हितग्राही जरूरत पड़ने पर अपने भू-खंड और कृषि भूमि को कलेक्टर की बगैर अनुमति के क्रय-विक्रय कर सकेगा। साथ ही बैंक से लोन भी मंजूर करवा सकेगा।

केंद्र सरकार की ओर से जून माह में भू-खंड पट्टे आवंटन के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसमें उन लोगों को पट्टे बांटने के लिए कहा गया है, जिनके पास स्वयं की न आवासीय भूमि है न कृषि भूमि। ऐसे में भू-खंड (आवास) के लिए आबादी सर्वे पहले करने को कहा गया है। इसकी प्रक्रिया भू-अभिलेख विभाग ने शुरू कर दी है। इसे लेकर सैटेलाइट के जरिए गांव चिह्नित किए गए हैं। अब धरातल पर पटवारियों द्वारा सत्यापन किया जा रहा है।

अब बगैर कलेक्टर की अनुमति हितग्राही पट्टों की जमीन खरीद-बेच सकेंगे

पहली बार मिलेगा भू-स्वामी का दर्जा

सरकारी जमीनों के अब तक बांटे गए पट्टों पर भूमि स्वामी की जगह शासकीय पट्टा दर्ज होता था जिसमें हितग्राही को भूमि को बेचने और खरीदने का अधिकार नहीं होता था। पहली बार केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले पट्टों में भूमि-स्वामी दर्ज किया जाएगा। इससे हितग्राही को जमीन के क्रय-विक्रय के साथ लोन लेने का अधिकार भी मिलेगा।

अब तक बैंक भी नहीं देते थे लोन

ऐसा नहीं है कि सरकार ने पहले भू-खंड व कृषि भूमि के पट्टे सरकारी जमीनों पर काबिज लोगों को नहीं बांटे। लेकिन इन पट्टों को शासकीय पट्टे के रूप में खसरे-खतौनी में दर्ज किया जाता था। ऐसे में हितग्राही को इस पट्टे से मिली भूमि को बेचने का अधिकार नहीं था। अगर किसी को जरूरत के मुताबिक बेचना भी होता तो उसके लिए लंबी प्रक्रिया करनी पड़ती थी। इसमें उसे कलेक्टर की अनुमति की जरूरत रहती थी। साथ ही इन सरकार पट्टों की खास बात यह थी कि सरकार व प्रशासन जब चाहे इन पट्टों का निरस्त कर जमीन वापस ले सकता था और हितग्राही को जमीन से बेदखल कर सकता था। साथ ही सरकारी पट्टे पर लोगों को बैंक भी लोन नही देता था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले भू-स्वामी के पट्टे से प्रशासन के यह सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे और भूमि पर सिर्फ हितग्राही को ही सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

टीकाकरण: कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार

डॉ. राजेश टिक्कस
मप्र इंडियन एकेडमी ऑफ पीडिट्रियाक्स के सचिव और जीएमसी, भोपाल में प्रोफेसर बाल्य एवं शिशु रोग विभाग

जैसा कि सर्वविदित है कि विगत 14-15 माह से हम सभी भारतवर्ष के लोग तथा संपूर्ण विश्व कोविड-19 नामक संक्रमण से गुजर रहा है। इस संक्रमण ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत प्रभावित किया है। इस बीच हमने कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के प्रकोप को भी सहा है। इस कोविड संक्रमण की अलग-अलग प्रकार की लहर के दौरान बहुत सारे लोगों के रिश्तेदारों, पारिवारिक सदस्यों तथा मित्र मंडली में से कई लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर हानि हुई है।

जैसा कि सर्वविदित है कि विगत 14–15 माह से हम सभी भारतवर्ष के लोग तथा संपूर्ण विश्व कोविड–19 नामक संक्रमण से गुजर रहा है। इस संक्रमण ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत प्रभावित किया है। इस बीच हमने कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के प्रकोप को भी सहा है। इस कोविड संक्रमण की अलग–अलग प्रकार की लहर के दौरान बहुत सारे लोगों के रिश्तेदारों, पारिवारिक सदस्यों तथा मित्र मंडली में से कई लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर हानि हुई है। कुछ प्रकरणों में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अत: दोस्तों, फिर यह बीमारी सर नहीं उठा सके, फिर हमें यह सब सहन न करना पड़े, फिर यह बीमारी विकराल रूप धारण न कर सके तथा वैसे दिन न देखना पड़े, इसके लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी आवश्यक है। जैसे विगत एक वर्ष से बातें भी हो रही हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इनमें सबसे पहला नियम ये आता है कि हमें सही तरीके से मास्क का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से साबुन से हाथों को धोना है तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है। सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए पब्लिक प्लेस में प्रत्येक व्यक्ति से दो गज की दूरी का ध्यान रखना है। इससे भी ज्यादा आवश्यक है कि जितना हो सके भीड़–भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। हमें पहले से भी ज्यादा अब इन सभी नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके अलावा जो बहुत बड़ा हथियार है जिससे इस कोविड–19 के संक्रमण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो है वैक्सीनेशन या टीकाकरण। टीकाकरण अर्थात कोविड से बचाव के लिए टीका लगवाना। हमारे देश में वर्तमान में कोविड से बचाव के लिए दो टीके उपलब्ध हैं। इनमें से एक वैक्सीन पूरी तरह से भारत में ही निर्मित हुई है तथा दूसरी का निर्माण भारत में हो रहा है। ये दोनों ही वैक्सीन कोविड संक्रमण से बचाव में कारगर है। इनके डोज की उचित मात्रा व दोनों डोज लगवाने पर कोविड संक्रमण से बहुत हद तक बचाव हो जाता है। जब हम टीकाकरण के द्वारा अपना बचाव कर लेते हैं तो परोक्ष रूप से हम दूसरों का भी कोविड संक्रमण से बचाव कर लेते हैं।

कोविड 19 से बचाव के लिए लगाई जा रहा वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारी सरकार हमारे स्वास्थ की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जागरूक है। वह लगातार प्रयासरत है कि इस बीमारी से हमारा बचाव हो सके। इस कार्य के लिए वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार है। अत:मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इस तरह न केवल आप कोविड संक्रमण से स्वयं का बचाव कर सकते हैं, बल्कि अपने परिजनों, मित्रों तथा मिलने–जुलने वालों एवं आस–पास के सभी लोगों को कोविड से बचाने के लिए अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। जब आप स्वयं संक्रमित नहीं होंगे तो आपके परिवार में छोटे बच्चे, अन्य परिजन तथा आपके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों तक कोविड संक्रमण आपके द्वारा संचारित नहीं होगा। जैसा कि हमें पता है कि वर्तमान में 18 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है तो 18 वर्ष और अधिक की आयु के लोग वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। वर्तमान में 18 वर्ष की आयु से कम अर्थात बच्चों के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है, जब इस आयु वर्ग का वैक्सीनेशन होगा, तब भी इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को टीका लगवाना चाहिए। जब हम खुद वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो गंभीर बीमारियां हमें नहीं होती हैं। किसी न किसी रूप में यह हमारे परिवार को भी सुरक्षित करता है।

परिवार के अन्य लोगों का यदि वैक्सीनेशन हो जाता है तो बच्चों को स्वयं ही इस संक्रमण से सुरक्षा मिल जाती है। प्राय: देखने में आ रहा है कि वैक्सीनेशन से संबंधित अनेक भ्रांतियां लोगों के बीच में फैली हुई है जैसे वैक्सीनेशन के उपरांत उन्हें गंभीर साइड इफेक्ट हो जाएंगे या उनके स्वास्थ पर विपरीत असर पड़ेगा वास्तव में ये भ्रांतियां निराधार हैं। इनके प्रमाण में कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। वैक्सीनेशन के कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है, हां कुछ साधारण साइड–इफेक्ट देखे जा सकते हैं जैसे हल्का बुखार आना, बदन दर्द होना तथा सरदर्द आदि जो 1–2 दिन में स्वत: ही ठीक हो जाते हैं। वैक्सीनेशन के दौरान ऐसा होना स्वभाविक बात है। ये साइड इफेक्ट भी सबको नहीं होते हैं। इस तरह के साइड इफेक्ट कई अन्य वैक्सीन में जैसे बच्चों को अन्य रोगों से बचाव के लिए लगाए जाने वाले वैक्सीन में भी देखे जाते हैं। ये उसी तरह के साइड–इफेक्ट है, जो बिल्कुल भी चिंताजनक नहीं है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वैक्सीन से हमें जो कोविड–19 जैसी गंभीर एवं जानलेवा बीमारी से सुरक्षा मिल रही है, उसकी तुलना में ये छोटे–छोटे साइड इफेक्ट बहुत ही नगण्य हैं। अत:मेरी सलाह है कि भांतियों में तथा तथ्यहीन अफवाहों में न आएं। बिना किसी झिझक के बेफिक होकर वैक्सीन लगवाएं तथा खुद को और अपने प्रियजनों को कोविड–19 के संक्रमण से बचाएं। वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टॉफ, नर्स तथा अन्य फ्रंटलाइन वर्कर जैसे पुलिस, आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी तथा अत्यावश्यक सेवाओं के लिए तैनात कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने टीका लगवाकर कोविड–19 से अपना बचाव कर लिया है। कोविड–19 संक्रमण से स्वयं को और खुद के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों हेतु वैक्सीन का सुरक्षा कवच सुनिश्चित कर वे 24 घंटे आपकी सेवा में उपस्थित हैं। अत: स्वयं के प्रति और अपने परिवार और समाज के प्रति इस वैश्विक आपदा के समय अपनी जिम्मेदारी निभाएं और टीका अवश्य लगवाएं। वैक्सीनेशन के उपरांत भी मास्क का नियमित उपयोग करना है। सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना है। भीड़–भाड़ वाले स्थानों में नहीं जाना है। इस तरह हम कोरोना वायरस के विरुद्ध हमारी जंग जीत सकते हैं।

विवि-कॉलेजों में अब पढ़ाया जाएगा एनसीसी का पाठ

कमांडर डॉ. ओम प्रकाश शर्मा
कमांडिग आफिसर, 1 एमपी नेवल यूनिट,एनसीसी भोपाल

एनसीसी का मुख्य उद्देश्य युवाओं में सशक्त चरित्र निर्माण, कामरेडशिप, अनुशासन, धर्म–निरपेक्ष दृष्टिकोण, अत्म–विश्वास, टीम–भावना, मूल्यनिष्ठ समाज, राष्ट्र–निर्माण एवम सेवाभाव के आदर्शों को विकसित करना है। एनसीसी प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व गुणों के साथ एक संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक ऐसा पूल बनाना है, जो राष्ट्रसेवा एवं राष्ट्र–निर्माण में सदैव अग्रणी रहेंगे चाहे वे किसी भी कैरियर का चयन करें। साथ ही, राष्ट्रीय कैडेट कोर युवा भारतीयों को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। एनसीसी ने 1948 से राष्ट्र–निर्माण में सतत रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा भारतीय युवाओं के लिए एनसीसी के पाठ्यक्रम को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने के लिए अनूठी पहल की है। इसके अंतर्गत अब विभिन्न विश्व–विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में एनसीसी को एक सुनियोजित पाठ्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है जिससे स्नातक परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में अन्य वैकल्पिक विषयों (जैसे विज्ञान, वाणिज्य, कला, विधि, संगीत, आदि) की ही तरह अब एनसीसी भी एक वैकल्पिक विषय के तौर पर उपलब्ध होगा। एनसीसी पाठ्यक्रम में कुल क्रेडिटों की संख्या 24 होगी जो कि 6 सेमिस्टर में विभाजित हैं। इसमें सामान्य विषयों के साथ मिलिट्री विषयों (आर्मी, नेवी, ऐयर फोर्स) की थ्योरी एवं प्रेक्टीकल क्लासेस ली जाएंगी। एक 10 दिवस का कैंप भी होगा, जिसमे पुरी ट्रेनिंग का सार होगा। विवि व कॉलेजों के प्रोफेसर्स (एएनओ) जहां सामान्य विषयों की थ्योरी क्लासेस लेंगे। वहीं एनसीसी इकाइओं के प्रशिक्षित एवं अनुभवी सैनिकगण (पीआईस्टाफ) मिलिट्री विषयों (आर्मी, नेवी, ऐयर फोर्स) की थ्योरी क्लासेस एवं प्रेक्टीकल क्लासेस लेंगे। इस समग्र एनसीसी पाठ्यक्रम में वार्षिक प्रशिक्षण शिविर भी शामिल हैं, जिनमें शामिल होना अनिवार्य है एवं अतिरिक्त क्रेडिट अंक भी दिए गए हैं। अब एनसीसी के पाठ्यक्रम को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने से छात्रों को संबंधित स्नातक डिग्री/मार्क्स शीट में समग्र सीजीपीए में एनसीसी (वैकल्पिक विषय) के क्रेडिट अंकों को भी दर्शाया जा सकेगा। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा यूजीसी को प्रस्ताव किया गया और प्रस्तावित समग्र नवीन एनसीसी पाठ्यक्रम भेजा गया है। फलस्वरूप यूजीसी की हरी झंडी के पश्चात यूजीसी द्वारा यह प्रस्ताव 15 अप्रैल 2021 को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजा गया है, जिसमें एनसीसी को उनके अंतर्गत सभी कालेजों में चल रहे स्नातक पाठ्यक्रमं में एनसीसी को भी शामिल करने के दिशा–निर्देश दिए गए हैं। महानिदेशालय द्वारा एनसीसी का नवीन पाठ्यक्रम नयी शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 एवं सामान्य वैकल्पिक क्रेडिट पाठ्यक्रम (सीबीसीएस) के अनुरूप बनाया गया है।

डब्ल्यूएचओ को सुधारने का समय

डॉ. सुरजीत सिंह,
अर्थशास्त्र के प्रोफेसर

विश्व व्यापार संगठन की तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारों में भी बढ़ोतरी आवश्यक हो चुकी है। यह अच्छा हुआ कि जी–7 देशों के मंच से इस पर जोर दिया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात डब्ल्यूएचओ कोरोना उत्पत्ति का पता लगाए। इस दबाव का नतीजा यह रहा कि डब्ल्यूएचओ प्रमुख को भी यह कहना पड़ा कि चीन कोरोना वायरस के स्रोत की तह तक पहुंचने में सहयोग करे। डब्ल्यूएचओ तभी से कठघरे में है, जबसे वह कोविड–19 महामारी को रोकने में नाकाम रहा। उसने कोविड–19 को महामारी घोषित करने में काफी समय लिया और समय रहते यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने के प्रति भी गंभीरता नहीं दिखाई। वुहान या चीनी वायरस नामकरण देने में झिझक उसकी भूमिका को और संदेहास्पद बना देती है। डब्ल्यूएचओ के चीन के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण ही पूरे विश्व में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इससे पहले 2015 के पश्चिमी अफ्रीका के इबोला संकट के समय में भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने में देरी के कारण उसे आलोचना का शिकार होना पड़ा था। डब्ल्यूएचओ के सदस्य देश उसे अनिवार्य एवं ऐच्छिक, दो प्रकार से फंड देते हैं। अनिवार्य योगदान के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य देश 1980 की जनसंख्या एवं जीडीपी के अनुपात में अपना योगदान देता है। डब्ल्यूएचओ के कुल बजट का लगभग 20 प्रतिशत अनिवार्य योगदान के रूप में प्राप्त होता है। जबकि ऐच्छिक योगदान के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य देश अपनी इच्छा से कितना भी दे सकता है। कुल बजट में इसका योगदान लगभग 35 प्रतिशत है, जिसमें सर्वाधिक 31 प्रतिशत योगदान अमेरिका का है। इसके बाद इंग्लैंड 16 प्रतिशत, जर्मनी 12 प्रतिशत एवं जापान का छह प्रतिशत का योगदान है। चीन का योगदान दो प्रतिशत है एवं भारत का एक प्रतिशत। यदि सदस्य देशों की ऐच्छिक एवं अनिवार्य राशि को मिला दिया जाए तो यह डब्ल्यूएचओ के कुल बजट का लगभग 50 प्रतिशत ही हो पाती है।

शेष बजट की राशि गैर सरकारी संस्थाओं से दान में प्राप्त होती है, जिसमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का सर्वाधिक लगभग आठ प्रतिशत का योगदान है। इस प्रकार डब्ल्यूएचओ को मिलने वाली कुल बजट राशि का लगभग दो तिहाई दान से प्राप्त होता है, जो इसकी नीतियों के निर्धारण में प्रत्यक्ष भूमिका का निर्वाह करते हैं। इनका सीधा संबंध दवाओं, टीकों एवं अन्य स्वास्थ्य उत्पादों के बाजार से जुड़ा है। इससे डब्ल्यूएचओ की वैधानिकता में निरंतर गिरावट आ रही है। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन को लोकतांत्रिक वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में अपनी वैधता को बनाए रखना है तो इसे अपने मूल कामों की तरफ लौटना होगा। इसे महामारी और स्वास्थ्य कवरेज जैसे मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोविड महामारी के बाद डब्ल्यूएचओ को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करना होगा। इसका मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा होती है, जिसमें सभी सदस्य देश हिस्सा लेते हैं। सदस्य देशों की प्राथमिकताएं अक्सर प्रमुख दानदाताओं के साथ टकराती रहती हैं। सदस्य देशों को स्वैच्छिक बजट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए डब्ल्यूएचओ के मुख्य बजट में अपने निर्धारित योगदान को बढ़ाना चाहिए। सदस्य देशों द्वारा गारंटीकृत फंडिग करने से न सिर्फ इसका कार्य विस्तार होगा, बल्कि सदस्य देशों के साथ तालमेल एवं जवाबदेही में भी वृद्धि होगी। डब्ल्यूएचओ को वित्त पोषण ढांचे में सुधार के अलावा अपने अतिरिक्त आय के स्रोतों में भी वृद्धि करनी होगी।

खरीफ मौसम में किसानों को कम लागत में होगा ज्यादा मुनाफा

औषधीय फसलों की खेती से बढ़ाएं आय

संवाददाता, भोपाल। जून-जुलाई के महीने में खरीफ फसलों की खेती होती है। बारिश के साथ ही किसान अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। खरीफमें आनी वाली फसलें पारंपरिक हैं। अगर आप इनसे हट कर कुछ अलग करना चाहते हैं तो किसानों के पास शानदार विकल्प हैं। तमाम औषधीय पौधे हैं, जिनकी खेती रोपाई या बोवनी का काम जून-जुलाई के महीने में होता है। सरकार भी किसानों की आय दोगुना करने के लिए पारंपरिक कृषि से हटकर नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। औषधीय पौधों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी मांग ज्यादा है और उत्पादन कम है। इस कारण किसानों को अच्छी कीमत मिलती है। खरीफ के मौसम में लगाई जाने वाली कुछ फसलें इस प्रकार हैं।

लेमनग्रास लेमन ग्रास एक औषधीय पौधा है। इसका इस्तेमाल मेडिसिन, कॉस्मेटिक व डिटरजेंट में किया जाता है। आप भी लेमन ग्रास की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेमन ग्रास खेती में न तो खाद की जरूरत होती है और न ही जंगली जानवरों के फसल नष्ट करने की डर रहता है।

सतावर सतावर या शतावरी आयुर्वेद में एक काफी महत्वपूर्ण पौधा है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सौ पत्ते वाला पौधा। यह भारत, श्रीलंका और पूरे हिमालय क्षेत्र में पाया होता है। सतावर की रोपाई जुलाई के महीने में की जाती है। एक एकड़ में 5-6 लाख रुपए तक की कमाई होती है। सतावर की खेती करने वाले किसानों को राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की ओर से 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

ब्राह्मी ब्राह्मी का पौधा पूरी तरह से औषधीय होता है। इसकी पत्तिया कब्ज दूर करने में मददगार होती हैं। वहीं इसके रस से गठिया का सफल इलाज होता है। ब्राह्मी में रक्त शुद्धी के गुण होते हैं। ब्राह्मी दिमाग को तेज करता है और यादाश्त बढ़ाने में भी सहायक होता है। इससे बनी दवाइयां का प्रयोग कैंसर, एनिमिया, दमा, किडनी और

मिर्गी जैसे बीमारियों के इलाज में किया जाता है। सांप के कांटने पर भी इसका इस्तेमाल होता है। इन्हीं वजहों से इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय बारिश का मौसम होता है।

एलोवेरा आज के समय में किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती कर रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एलोवेरा का व्यावसायिक रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। एलोवेरा की रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय जुलाई से अगस्त का होता है। इस मौसम में रोपाई करने से पौधे पूरी तरह जीवित रहते हैं और पैदावार अच्छी होती है। किसान बताते हैं कि एक एकड़ में आसानी से दो लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है। एलोवेरा के पौधे जुलाई-अगस्त में लगाना उचित रहता है।

कौंच कौंच भारत के लोकप्रिय औषधीय पौधों में से एक है। यह भारत के मैदानी इलाकों में झाड़ियों के रूप में विकसित होता है। इस झाड़ीनुमा पौधे की पत्तियां नीचे की ओर झुकी होती हैं। इसके भूरे रेशमी डंठल 6 से 11 सेंटी मीटर लंबे होते हैं। इसकी बोवनी बीज से होती है और बारिश से पहले इसकी खेती को सबसे उपयुक्त माना जाता है। कौंच की खेती खरीफ में की जाने वाली एक फसल है, जिसके लिए अनुकूल समय 15 जून से 15 जुलाई तक का होता है। कौंच के पौधे के सभी भागों में औषधीय गुण होते हैं। इस की पत्तियों, बीजों व शाखाओं का इस्तेमाल दवा के तौर पर किया जाता है इस तरह कम लागत में अच्छी आमदनी देने वाली खेती के रूप में कौंच की खेती करना आज के समय में एक अच्छा विकल्प है।

» खरीफ फसल बोवनी की तैयारियां शुरू

» किसानों को नहीं मिल रहा प्रमाणित बीज

» किसानों को नहीं मिला रहा सोयाबीन

एमपी में उड़द, ज्वार और मक्का का बढ़ेगा रकबा

संवाददाता, भोपाल

सोया स्टेट कहे जाने वाले मप्र में सोयाबीन का प्रमाणित बीज नहीं मिल पा रहा है। जिन व्यापारियों के पास सोयाबीन का स्टॉक रखा है वह 9 हजार रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उसे बेच रहे हैं, लेकिन अंकुरण की कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। बीज निगम और सोसायटियों के पास भी प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं है। इस कारण किसान उड़द, ज्वार और मक्का की खेती पर फोकस कर रहे हैं। इससे प्रदेश में इस बार सोयाबीन का रकबा घट सकता है। जिन किसानों ने खेत की मिट्टी पलटने के लिए पिलाउ कराया था। उन्होंने अब खेत को तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा जिन खेतों से किसानों ने हार्वेस्टर के माध्यम से गेहूं की फसल कटाई की थी उनमें गेहूं के पौधे के जो अवशेष खड़े हुए थे मानसून पूर्व हुई अल्प और जोरदार बारिश से खेतों की हकाई जुताई का रास्ता साफ हो गया है। बारिश से पूर्व बोवनी की तैयारी कर रहे हैं। इससे मौका देख कर फसल बोवनी प्रारंभ की जा सके। इसी के चलते खाद बीज डीजल का भी स्टॉक कर रहा है।

मंडी में 6800 रुपए क्विंटल सामान्य भाव

वर्तमान में कृषि मंडी में सोयाबीन का भाव 6800 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। जिन लोगों के पास सोयाबीन का स्टॉक रखा है, उन्होंने भी सोयाबीन किसानों से ही खरीदा है। इसी को छानबीन कर कतिपय स्टॉकिस्ट बीज के रूप में 9000 रुपया प्रति क्विंटल दे रहे हैं। पिछले सालों के दौरान किसानों ने बाजार से जो बीज खरीदा था। खेतों में अंकुरित नहीं हुआ था।

सोयाबीन का फाउंडेशन बीज तो आता ही नहीं

सोयाबीन का फाउंडेशन बीच कभी आता ही नहीं। बीज निगम भी बीज निर्माता पंजीकृत सोसायटियों से खरीद कर लाती है। पिछले सालों के दौरान बीज निगम और सहकारी सोसाइटियों द्वारा खरीदा गया बीज अंकुरित नहीं हुआ था। इसके चलते किसानों को परेशान होना पड़ा था। शिकवा शिकायत के कारण कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा था। इसके कारण सोसाइटियों ने डिमांड भेजना बंद कर दी। बीज निगम पर फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

30 जून से पहले भर दें कर्ज वरना देना होगा 3 फीसदी ब्याज

निधि का लाभ पाने वाले किसानों का केसीसी बनाया जा रहा

संवाददाता, भोपाल

यदि आप किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हुए यदि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का भी लाभ ले रहे हैं तो तत्काल अपना ऋण चुका कर ज्यादा ब्याज दरों के भुगतान से बच सकते हैं। दरअसल, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पाने वाले किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भी बनाया जा रहा है। किसानों को इस केसीसी पर आसान और सस्ता कर्ज मिलता है। केंद्र सरकार ने बीते साल ही निर्देश दिया था कि किसान सम्मान निधि का लाभ पाने वाले सभी किसानों को केसीसी का भी लाभ दिया जाए। इसका विशेष लाभ ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर मिला लोन तभी तक सस्ता रहेगा जब केसीसी लोन की शर्तों का पालन किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो ज्यादा ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है।

खेती के लिए लोन

यदि आपने भी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लिया है तो उसे जमा करने के लिए आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि 30 जून तक इसे जमा करना होगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए गए ऋण को यदि समय पर चुका दिया जाता है तो किसानों को सिर्फ 3 फीसदी ब्याज ही देना होता है और यदि किसानों ने इस बार यह ऋण 30 जून के बाद चुकाया तो 7 फीसदी ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है।

सरकार दो बार बढ़ा चुकी तारीख

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से आर्थिक

गतिविधियां काफी प्रभावित हुई है। ऐसे में किसानों की आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित हुई है और सरकार ने किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन की रकम को जमा करने की तारीख दो बार बढ़ाई थी। इसे तय तारीख 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दिया था, लेकिन फिर बाद में इसे 31 अगस्त 2020 कर दिया गया। इस साल 2021 में भी सरकार ने 3 महीने की मोहलत दी है। 30 जून तक लोन की रकम सबको जमा करनी होगी।

किसानों को मिलता है 3 लाख

किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए तीन लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। गौरतलब है कि लोन पर ब्याज 9 फीसदी है, लेकिन केसीसी पर सरकार 2 फीसदी सब्सिडी देती है। इससे केसीसी पर किसान को 7 फीसदी ब्याज पर लोन मिलता है। साथ ही किसानों को यह लाभ भी मिलता है कि किसान अगर समय से पहले लोन चुका देते हैं तो किसानों को सिर्फ 4 फीसदी ब्याज ही देना होता है। समय पर लोन जमा करने पर 3 फीसदी तक छूट मिलती है।

हर मौसम में ले सकेंगे ताजी सब्जी-भाजी और फलों का स्वाद

» 12 जिलों में बनाए जा रहे 5 से 10 हेक्टेयर के क्लस्टर » ग्रीन हाउस में अब हर मौसम में उग सकेंगी सब्जियां

संवाददाता, भोपाल

सर्दी के मौसम में होने वालीं गोभी, पालक, हरी मटर, मैथी, शिमला मिर्च जैसी सब्जियों का स्वाद गर्मी में भी आराम से मिल सकेगा। फल और फूल भी खरीद सकेंगे। यह होगा ग्रीन हाउस में बेमौसम सब्जी की खेती से किसानों को बड़े ग्रीन हाउस बनाने सरकार 60 फीसदी तक अनुदान देगी। इस तरह की सब्जियों को उपयुक्त तापमान देने उपकरणों पर भी अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश में बेमौसम सब्जी, फूलों की खेती के लिए 12 क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। एक जिले में पांच से दस हेक्टेयर तक का क्लस्टर होगा। हर जिले में ग्रीन हाउस, पॉली हाउस तैयार करने लगभग 70 लाख का बजट रखा गया है। इसमें टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी, ब्रोकलिन, बैंगन, तरबूज, खरबूज, स्ट्रॉबेरी और फूलों की खेती को शामिल किया गया है।

किसानों की होगी समिति

इन क्लस्टर में किसानों की अपनी समिति होगी। जहां से वे माल लाकर शहरों में बेच सकेंगे। समिति के माध्यम से ही सब्जी और फल के परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह आपस में मिलकर कारोबार का संचालन कर सकेंगे। इसी के चलते उद्यानिकी विभाग एक क्लस्टर में सिर्फ एक तरह की सब्जी, फल की खेती के लिए चयन करेगा।

कम लागत में ज्यादा पैदावार

क्लस्टर में फल-फूल, सब्जी की खेती ज्यादा से ज्यादा किसानों से कराई जाएगी। जिससे उन्हें कम लागत, कम परिवहन व्यय और कम तकनीक में ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिल सके। किसानों को प्रशिक्षण के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। जब एक तरह की सब्जी और फल उगाने वाले किसान एक है क्षेत्र के होंगे तो उन्हें खेती करने के संबंध में प्रशिक्षण पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा।

ये जिले शामिल

प्रदेश में बेमौसम सब्जी, फूलों की खेती के लिए भोपाल, देवास, सीहोर, इंदौर, खंडवा, शाजापुर,छिंदवाड़ा, बैतूल,अलीराजपुर, शिवपुरी,बालाघाट, कटनी जिले में 12 क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। सरकार का फोकस है कि इन जिलों में सफलता मिलने के बाद अन्य सभी जिलों में क्लस्टर बनाए जाएंगे।

भोपाल जिले की 4 पंचायतों के 13 गांवों ने लिया फैसला

जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा, उसके परिवार का हुक्का-पानी बंद

संवाददाता, भोपाल

ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने के अनोखे प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीणों के मन में वैक्सीनेशन के प्रति डर और भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही प्रयास भोपाल की 4 पंचायतों के 13 गांवों में शुरू हुआ है। यहां ग्रामीणों ने तय किया है कि जो भी गांव का व्यक्ति कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएगा, उसके पूरे परिवार का बहिष्कार किया जाएगा। वैक्सीन के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए रातीबड़, सरवर, सिकंदराबाद, मुंडला, पंचायतों के गांवों में ग्रामीणों ने जागरूकता अभियान की पहल की है। सरवर ग्राम पंचायत के मंडल अध्यक्ष मनोज कामवार का कहना है कि पंचायत में वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में डर है। ग्रामीण कहते हैं कि इसको लगवाने से मौत हो रही है। महिलाओं को डर है कि व्यक्ति लगवाने से बच्चे पैदा नहीं होंगे। इन्हीं सब भ्रांतियों को दूर करने जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि यदि वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। गांव में जगह- जगह जागरूकता को लेकर पोस्टर भी लगाए गए हैं।

घर-घर दिए जा रहे पीले चावल

वैक्सीनेशन के प्रति ग्रामीण जागरूक हो इसके लिए प्रशासन गांवों में पीले चावल भी बटवा रहा है। गांव में घर-घर पीले चावल देकर वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को निमंत्रण पत्र भी बांटे जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द बड़ी संख्या में ग्रामीणों का टीकाकरण किया जा सके।

जागरूकता अभियान का दिख रहा असर

सरवर ग्राम पंचायत के सरपंच लाल सिंह मीणा का कहना है कि वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों के चलते लोग वैक्सीनेशन टीम को देखकर घर के दरवाजे बंद कर लिया करते थे। अफवाहों और डर को दूर करने गांव में वैक्सीन लगाओ-जान बचाओ अभियान की शुरुआत हुई है। गांव में 1500 लोगों की आबादी है जिसमें से अब तक सिर्फ 400 लोगों ने ही टीका लगवाया है। जागरूकता अभियान के बाद अब लोग धीरे-धीरे वैक्सीन लगवाने टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। टीका लगवा चुके ग्रामीण लोगों को वैक्सीन से मौत की अफवाहों से दूर रहने को लेकर घर-घर जाकर जागरूक भी कर रहे हैं।

'राम' की बगिया में संजीवनी

» सतना के किसान सब्जियों के देसी बीज और जड़ी-बूटी के संरक्षण में जुटे

» किसान की बगिया में वर्तमान समय में 250 से ज्यादा औषधीय पौधे

संवाददाता, सतना

पक्के मकान की एक दीवार पर लटकी कई आकार की सूखी लौकियां और सब्जियों की फलियां अक्सर यहां आने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इस मकान और इसके आसपास ऐसा बहुत कुछ और भी है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। दरअसल, ये किसान राम लोटन कुशवाहा का देसी म्यूजियम है, जिसमें वो जैव विविधता को सहेज रहे हैं। देसी सब्जियों और जड़ी-बूटियों से मुझे इतना स्नेह है कि दिन-रात कब ढल जाते हैं, इसका पता नहीं लग पाता। राम लोटन कुशवाहा, देसी सब्जियों और जड़ी बूटियों के संरक्षण के प्रति अपनी दीवानगी बताते हैं। राम लोटन (64 वर्ष) दिल्ली से करीब 750 किमी दूर मध्य प्रदेश के सतना जिले उचेहरा ब्लॉक के गांव अतरवेदिया के निवासी हैं। उनका गांव जिला मुख्यालय सतना से 25 किमी दूर है। यहीं पर रामलोटन एक एकड़ कुछ कम खेत में औषधीय गुणों से भरी जड़ी बूटियों का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं। साथ में हर साल कई तरह की सब्जियां उगाते हैं।

250 औषधीय पौधे

राम लोटन की बगिया में मौजूदा समय में 250 से भी अधिक औषधीय पौधों का अनुपम संग्रह है। यह यहां संवर्धित हो रहे हैं। इसके अलावा 12 प्रकार की लौकियां, गाय के मुंह के आकार के बैगन आदि हैं।

अलग-अलग नाम: राम लोटन बताते हैं कि लौकियों को उनके आकार के आधार पर नाम दिए गए हैं। जैसे अजगर लौकी, बीन वाली लौकी, तंबूरा लौकी आदि इनमें से कुछ खाने के काम आती हैं बाकी की लौकियों का औषधीय उपयोग किया जा रहा है। इससे पीलिया, बुखार ठीक किया जाता है।

इन पौधों का संग्रह

बगिया में सिंदूर, अजवाइन, शक्कर पत्ती, जंगली पालक, जंगली धनिया, जंगली मिर्चा के अलावा गौमुख बैगन, सुई धागा, हाथी पंजा, अजूबी, बालम खीरा, पिपरमिंट, गरूड़, सोनचट्टा, सफेद और काली मूसली और पारस पीपल जैसी तमाम औषधीय गुण के पौधे रोपे गए हैं।

हिमालय से ले आए ब्राम्ही

जड़ी बूटियों को खोजने के लिए राम लोटन कहीं भी जा सकते हैं। ब्राम्ही के लिए हिमालय तक गए थे। वो बताते हैं कि लोग कहते रहे कि हिमालय के पौधे यहां कैसे हो सकेंगे? लेकिन मेरी बगिया में सब कुछ वैसा ही फल-फूल रहा है। इसके अलावा अमरकंटक सहित अन्य जंगलों में भी भटके हैं।

जड़ी बूटी सुई धागा भी है...

रामलोटन के मुताबिक उनके पास सुई धागा नामक की एक जड़ी बूटी है। इस जड़ी-बूटी के बारे में वो बताते हैं, राजाओं के जमाने में तलवारें जब लड़ाइयों में चलती थी तो कट जाना सामान्य था। कहा जाता है यही सुई धागा घाव भरने का काम करती थी। बस इसे काट लें और दूध के साथ बांट लें। जहां कटा है वहां लगा लें, कुछ ही घंटों में इसका असर दिखाई देने लगता है।

बैगाओं ने बताए जड़ी बूटियों के राज

राम लोटन बताते हैं कि बैगाओं से इसकी जानकारी ली है। वो जंगल में होने वाली आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी बखूबी रखते हैं। उनसे मिलने जाता रहता हूं। वह भी मेरे पास आते रहते हैं। बालाघाट, उमरिया, शहडोल, निमाड़, भिंड आदि जिलों के अलावा और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बस्तर के इलाकों में रहने वाले बैगाओं से जड़ी बूटियों की पहचान और गुण की जानकारी लेता रहता हूं। यहीं परसमनिया पठार में भी बैगा रहते हैं वह भी बताते रहते हैं।

नर्सरी में सफेद पलाश

कुशवाहा इसी तरह कई अन्य जड़ी बूटियों का उपयोग भी बताते हैं। उनकी नर्सरी में सबसे खास सफेद पलाश है जो बहुत कम ही देखने को मिलता है। सफेद पलाश को बचाने के लिए वो उसकी नई पौध भी तैयार करे हैं। इसे देखने और पौध लेने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं।

खेतों में खड़ी और पड़ी अरबों की मूंग डूबी

»किसानों के लिए फिर बारिश बनी आफत »धूप नहीं निकली तो काट कर रखी उपज में हो जाएगा अंकुरण

संवाददाता, भोपाल

अन्नदाता की खुशियों को प्री मानसून की तेज बारिश ने ग्रहण लगा दिया है। कटाई के लिए तैयार और खेतों में काट कर रखी गई अरबों रुपए मूल्य की मूंग बारिश के पानी में डूब गई है। अगर धूप नहीं निकली तो काट कर रखी उपज में अंकुरण हो जाएगा।

उधर, मौसम विभाग ने प्रदेश के कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश की संभावना जताकर किसानों को पसोपेश में डाल दिया है। कृषि विभाग के अनुसार, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर सहित जिन क्षेत्रों में मूंग है, वहां के किसानों के लिए प्री मानसून की बारिश आफत बन गई है। पिछले दो-तीन दिन की बारिश में जो फसल भिगी है उसमें से 50 फीसदी मूंग खराब होने का अनुमान है। सबसे ज्यादा नुकसान उन किसानों को हुआ है जो खेतों में पक कर खड़ी मूंग को काटने की तैयारी में थे या काट कर रहे थे। अचानक बारिश होने से जहां पकी हुई मूंग खराब हो गई है तो गाहनी की जा रही फसल भी खराब हुई है।

तीन जिलों में ज्यादा नुकसान

प्रदेश में मूंग के उत्पादन में होशंगाबाद पहले, हरदा दूसरे और नरसिंहपुर तीसरे स्थान पर है। इन जिलों में इस बार ग्रीष्मकालीन मूंग की बंपर पैदावार हुई थी, लेकिन किसानों की मेहनत पर प्री मानसून की भारी बारिश ने पानी फेर दिया है। किसानों के अनुसार इससे बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। एक ओर किसान शासकीय समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने के पंजीयन कराने में लगा हुआ है। वहीं बरसात से हुए नुकसान के बाद किसान संगठन एवं किसान शासन से नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजे की मांग भी करने लगे हैं।

15 जून से मूंग की खरीदी

शासन ने हाल ही में 7196 रुपए प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर इसकी खरीदी की घोषणा की थी। 15 जून से मूंग की खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन पानी ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। मूंग की औसत उपज प्रति हेक्टर 16 क्विंटल तक प्राप्त हुई है। केवल 2 महीने की मेहनत वाली यह फसल जब किसानों को उनकी मेहनत का मीठा फल देने वाली थी तो प्री मानूसन ने किसानों को रुला दिया।

बारिश से हुआ नुकसान

इस बार बारिश एक सप्ताह पहले ही होने लगी है जिससे किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। पिछले सालों में मानसूनी बारिश का रिकार्ड देखें तो 20 जून के आसपास बारिश होती रही। किसान पिछले सालों की बारिश के हिसाब से मूंग की कटाई गाहनी आदि की तैयारी कर रहे थे पर प्री मानसून काफी ताकत से आया और किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ।

कमजोर हो जाएगी चमक

दाने खराब होने के साथ ही चमक कमजोर हो जाएगी। जिससे एफएक्यू के दायरे में नहीं आ सकेगी। किसानों का कहना है कि इस बार मूंग की फसल अच्छी होने से अब लग रहा था कि पैदावार अच्छी होगी। लेकिन अब इस बारिश ने अच्छी उम्मीद पर पानी फेर दिया है। सिर्फ चार दिन और मानसून नहीं आता तो किसानों की पूरी मूंग बच जाती।

कटाई में भी समस्या

मूंग की फसल में ज्यादा पानी पहुंचने के कारण उसके फलीदार पौधे झुक गए हैं। वह खेत से चिपक गए हैं। जिससे अब कटाई में देरी के साथ ही कटाई की समस्या आ रही है। क्योंकि हारवेंस्टर से काटते समय फसल के साथ मिट्टी भी आ जाएगी। मानसून का असर बना हुआ है। जो हल्का होता जा रहा है फिर भी अभी एक दिन और इसी प्रकार रुक रुककर बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। बारिश का दौर पूरे जिले में रुक रुककर बना हुआ है। जिससे नुकसान हो रहा है।

फसल के पंजीयन में हो रही गड़बड़ी

इधर, शासन ने भले ही मूंग की एमएसपी तय कर दी हो लेकिन जिले के किसान एमएसपी पर मूंग नहीं बेच पा रहे हैं। दरअसल मूंग के लिए किसान पंजीयन ही नहीं करवा पाए हैं, जबकि अंतिम तिथि 16 जून तक ही थी। अब किसानों के सामने अपनी फसल एमएसपी पर नहीं बेच पाने का संकट उत्पन्न हो रहा है। किसानों के खसरों में सरसों, गेहूं, धान, ज्वार व बाजरा के कॉलम थे, जबकि मूंग दर्ज करने के लिए विकल्प ही नहीं दिया गया था। ऐसे में संबंधित हल्के के पटवारी मूंग की फसल किसानों के खसरे में दर्ज नहीं कर पाए। लिहाजा एमएसपी पर मूंग फसल विक्रय करने के लिए किसानों की उम्मीदें फीकी पड़ती नजर आ रही हैं। शासन भले ही मूंग की फसल को बेचने के लिए सरकारी रेट निर्धारित कर दिए हो। परंतु किसान सरकारी रेट का फायदा नहीं ले सकेंगे। कारण यह है कि मूंग की फसल का पंजीयन किए जाने में गड़बड़ी है। खसरा में मूंग की फसल का कॉलम ही नहीं था। फसल को सरकारी रेट पर बेचने का किसान फायदा नहीं उठा सकेंगे।

किसान मूंग की फसल को एमएसपी पर कैसे बेचेंगे

एमएसपी पर 7195 रुपए क्विंटल

सरकारी खरीद पर मूंग का समर्थन मूल्य 7195 रुपए प्रति क्विंटल है जबकि मंडी में बेचने पर किसान को प्रति क्विंटल 5500 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। ऐसे में एमएसपी पर मूंग नहीं बिक पाने पर किसान को प्रति क्विंटल पर 1695 रुपए का नुकसान होगा। शासन स्तर पर मूंग फसल के लिए खसरे में विकल्प दिए बिना ही पंजीयन शुरू कराने की घोषणा कर दी गई है जो किसानों के लिए नामाकूल साबित हो रहे है।

चंबल के बीहड़ में बीज उगाएगा बीज निगम

»केंद्रीय बीज निगम के निदेशक ने लिया जायजा »अगर जमीन मिल गई तो चंबल में उगेंगे तिलहनी बीज

मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम MPSEEDS

संवाददाता, भोपाल

केन्द्रीय बीज निगम की नजर चंबल के बीहड़ पर है। निगम वहां तिलहन बीज उगाने की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए लगभग सात हजार हेक्टेयर जमीन चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर शासकीय भूमि नहीं मिल पा रही है। लिहाजा अब निगम की नजर मुरैना के चंबल के बीहड़ पर है। निगम बीहड़ को समतल बनाकर उसमें बीज पैदा करने की प्लानिंग कर रहा है। गत दिनों केन्द्रीय बीज निगम के निदेशक एवं भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अश्वनी कुमार, बीज निगम के निदेशक वाणिज्य एम एल अरोरा तथा भोपाल रीजन के रीजनल मैनेजर गुलबीर सिंह सहित अन्य अधिकारी मुरैना पहुंचे और संभावनाओं को तलाशा। गौरतलब है कि यह प्रोजेक्ट केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा प्रस्तावित है। केन्द्रीय मंत्री चाहते हैं कि बीहड़ की शक्ल बदले जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिल सके। केन्द्रीय बीज निगम को लगभग 7 हजार हेक्टेयर जमीन बीज उगाने के लिए चाहिए, जो केवल बीहड़ में ही मिल सकती है।

एक माह पहले आया था दल

लगभग एक माह पहले सीएससी सेन्ट्रल बीज कॉरपोरेशन(केन्द्रीय बीज निगम) का एक दल मुरैना आया था। दल का नेतृत्व रीजनल मैनेजर गुलबीर सिंह कर रहे थे। दल के सदस्य सबलगढ़ व चंबल के कुछ क्षेत्रों में शासकीय भूमि देखने गए थे। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर निगम को बीज उगाने के लिए जगह चाहिए वह नहीं मिली थी। लिहाजा अब, निगम की नजर चंबल के बीहड़ पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सरकार ने चंबल की जगह दे दी तो वहां निगम द्वारा तिलहन बीज उगाए जाएंगे।

बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार

केन्द्रीय बीज निगम तिलहनी बीज उगाने के साथ-साथ बड़े स्तर पर बड़े-बड़े गोदाम भी बनाएगा। इन गोदामों में काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। इससे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। किसानों को भी रोजगार मिलेगा। किसान अपने द्वारा उगाई गई तिलहन फसल को यहां बेच सकेंगे। दैनिक भास्कर इस खबर को लगातार अपडेट कर रहा है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रशासन तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, ज़ोन-1, भोपाल, म.प्र.

संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)